ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

28 जून, 2018 • वर्ष 1, अंक 23

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनपद कन्नौज में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करते हुए

- मगहर में स्थापित होगी संत कबीर अकादमी
- सरकारी विद्यालयों में लगेगें वाटर एटीएम
- अयोध्या नगरी को मिलेगी वैश्विक पहचान
- आम से बनने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की होगी ब्रांडिंग
- जे.ई.और ए.ई.एस. पर नियंत्रण को तैयार है सरकार
- मुख्यमंत्री जी का संकल्प निर्मल होगी गोमती

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

नदियों की अविरलता और निर्मलता बनाये रखना सृष्टि के हित में आवश्यक

सरयू जी का बड़ा पौराणिक महत्व है। भगवान राम की जन्म स्थली से जुड़ी हुई पवित्र नदी होने के नाते यह देव नदी भी कहलाती है। लोग अपनी पवित्रता को बनाये रखने के लिए सरयू जी में डुबकी लगाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने प्रयास प्रारम्भ किया है कि अयोध्या में सरयू जी के प्रत्येक घाट पर इसकी अविरल व निर्मल धारा पूरे वर्ष प्रवाहित होती रहे।

मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में श्री सरयू जयंती महोत्सव के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरयू जी में कोई भी गन्दा नाला किसी भी शहर या कस्बे का न गिरे। इसके लिए यहां के सभी नालों को ट्रेप करते हुए इसे एस.टी.पी. में गिराने की व्यवस्था तथा सरयू की एक अविरल और निर्मल धारा राम की पैड़ी होते हुए दशरथ समाधि की ओर बढ़ सके, इस दिशा में एक नया सर्वे करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर गुप्तार घाट के पास डैम बनाया जाएगा, जिससे अयोध्या को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह आवश्यक है कि सरयू जी की अविरलता और निर्मलता के लिए सब मिलकर कार्य करें और अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलायें। दुनिया के अन्दर अयोध्या की पहचान उसी रूप में हो जिस रूप से पूरी दुनिया का सनातन धर्मावलम्बी इसको देखना चाहता है। एक स्वच्छ और सुन्दर अयोध्या, एक ऐसी अयोध्या हो जहां सब कुछ रामराज की परिकल्पना का साकार प्रतिरूप हो। राज्य सरकार अयोध्या के सर्वागीण विकास तथा सरयू जी की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए प्रतिबद्ध है।

अयोध्या नगरी को मिलेगी वैश्विक पहचान : मुख्यमंत्री

राज्य सरकार व केन्द्र सरकार प्राचीन व आध्यात्मिक नगरी अयोध्या के सर्वागीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। अयोध्या को वैश्विक स्वरूप व पहचान देने के साथ–साथ भव्य तथा सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार अयोध्या में विराट संत सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष अयोध्या में छोटी दीपावली के दिन भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया। राम–सीता और लक्ष्मण के स्वरूप जब पुष्पक विमान से रामकथा पार्क पर उतरे, तो प्राचीनतम चित्र लोगों के नेत्रों में सजीव हो गया।

प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों से स्थापित किये सांस्कृतिक सम्बन्ध

प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से दुनिया के 192 देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुम्भ को वैश्विक मान्यता मिले इसके लिए यूनेस्को के मानचित्र पर प्रयागराज को स्थापित किया है। वर्तमान सरकार ने वनवासी, दलितों, वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है और उन्हें प्रदेश व केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया है।

अयोध्या नगरी का सर्वागीण विकास है सरकार का लक्ष्य

सरकार द्वारा अयोध्या नगरी का विकास प्रारम्भ हुआ है। 5, 14, व 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास के साथ यहां के प्रति लोगों की आस्था से समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या के सर्वागीण विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही हैं।राम की पैड़ी का विकास हो सरयू मैय्या का स्वच्छ निर्मल, अविरल व पवित्र जल सभी घाटों पर रहे इसकी वृहद कार्य योजना तैयार है। सभी नालों को सरयू में गिरने से रोकने के बाद नालों का पानी एस.टी.पी. पर डालने की योजना है।

सरकार ने अयोध्या की निरन्तर रामलीला, सरयू आरती, चित्रकूट में कीर्तन आदि सभी परम्पराओं को पुनर्जीवित किया है। अयोध्या के समग्र विकास का कार्य हो रहा है, साफ–सफाई, बिजली के तारों को अण्डरग्राउण्ड करना, अयोध्या को नगर निगम का दर्जा देने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया। इस प्रयास का उद्देश्य देश व प्रदेश के धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।

–मुख्यमंत्री

सूचना का अधिकार एक क्रांतिकारी अधिनियम है जो यथास्थिति में परिवर्तन लाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम ने शक्ति संतुलन को जनता के पक्ष में सशक्त किया है। अधिनियम के लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं जिसमें आम जनता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत केवल सूचना अधिकारियों का ही नहीं बल्कि सूचना मांगने वालों तथा आम जनता का भी समय-समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। वर्ष 2015 में नियम बनाए गए तथा उसका प्रख्यापन हुआ। सरकार में पारदर्शिता नहीं होती है तो भ्रष्टाचार पनपता है। सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन स्थापित करने तथा भ्रष्टाचार को दूर करने का माध्यम है।

–राम नाईक

राज्यपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम है पारदर्शिता लाने का प्रबल शस्त्र

महिला शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का चित्र बदल रहा है। यह बदलता हुआ चित्र पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किए गए 'सर्व शिक्षा अभियान' तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना का नतीजा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता लाने का प्रबल शस्त्र है। इस अधिकार को समाज के हित के लिए उपयोग में लाया जायेगा। देश की सुरक्षा को छोड़कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत हर जानकारी अधिकृत रूप से मिल सकती है। इस अधिनियम की वजह से मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी प्रमाणिकता से काम कर सकेंगे, क्योंकि यह सबको मालूम है कि इस कानून के अंतर्गत कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्व को महसूस करेंगे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में फेडरेशन ऑफ ओब्सट्रेटिक एण्ड गायनक्लोजिक्ल सोसायटी ऑफ इण्डिया (फाग्सी) के तत्वावधान में आयोजित आर.टी. आई. वर्कशाप के उद्घाटन के अवसर पर यह उद्गार व्यक्त किए।

दुरूपयोग पर अंकुश है जरूरी

आम आदमी को जानकारी लेने का अधिकार है और सरकारी कर्मचारी को सूचना देने की जिम्मेदारी है। कुछ लोग इस अधिकार का प्रयोग सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। सूचना के अधिकार का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। दुरूपयोग करने वालों पर भी अंकुश लगना चाहिए।

नियमावली प्रख्यापित होने से प्रदेश में अधिनियम का हो रहा है प्रभावी उपयोग

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा सूचना के अधिकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अधिनियम तब तक व्यवहार में नहीं आता जब तक उसके नियम प्रख्यापित न हो जायें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया, परन्तु उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार की नियमावली न होने के कारण यह उतना उपयोगी नहीं हो सका था। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा नियमावली प्रख्यापित कराई गई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में अधिनियम का प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है। जवाबदेही और पारदर्शिता की दृष्टि से 1978 से विधायक से राज्यपाल रहते हुए राम नाईक जी हर वर्ष जनता को अपना वार्षिक कार्यवृत्त प्रस्तुत करते हैं। ■

आम से बनने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की होगी ब्रांडिंग : मुख्यमंत्री

वर्तमान सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कृतसंकल्पित है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए किसानों को नई तकनीक से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध कराए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पर्यटन विभाग तथा मण्डी परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, 2018' के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य आम की विभिन्न प्रजातियों से जनमानस को परिचित कराना तथा आम की किस्मों का संवर्धन और संरक्षण करना है। आम महोत्सव को केवल राजधानी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि जनपद स्तर तक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

किसानों को परम्परागत खेती के साथ–साथ फल, फूल, पशुपालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में भी जुड़ने की जरूरत है। तभी किसान समृद्ध होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आधुनिक बागवानी करने वाले किसानों को अंग वस्त्र व प्रशंसा–पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदर्शनी में उत्तराखण्ड तथा मध्य प्रदेश के बागवानों ने भी आम की विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन किया।

आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। प्रदेश में लगभग 2.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम के बाग हैं, जिससे लगभग 40 से 45 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप आम का उत्पादन किया जाए, जिससे किसान आमों का निर्यात कर लाभ कमा सकें।

प्रदेश में आम की लगभग 700 प्रजातियां पायी जाती हैं। आवश्यकता इस बात है कि इन आमों की प्रजातियों के संरक्षण व संवर्धन के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण पर बल दिया जाएगा। आम से बनने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों अचार, स्क्वैश, जूस, अमावट आदि की ब्रांडिंग की जायेगी, जिससे किसान वर्षभर अपनी उपज का लाभ ले सकता है।

> प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया गया। पहले किसानों को डीजल से पम्पिंग सेट चलाने में 25 रुपए का खर्च आता था, वहीं वर्तमान सरकार के प्रयासों से अब बिजली के माध्यम से मात्र एक रुपए खर्च होता है।
>
> **–योगी आदित्यनाथ**

जे.ई.और ए.ई.एस. पर नियंत्रण को तैयार है सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ए.ई.एस व जे.ई. रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने इन रोगों के बचाव के लिए पूरी तैयारी समयबद्ध ढंग से किए जाने के निर्देश दिए हैं।

जनसामान्य में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जुलाई माह में इन रोगों के विरुद्ध जागरूकता और प्रचार–प्रसार का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जनपदों विशेषकर गोरखपुर तथा बस्ती मण्डलों के जनपदों की पी.एच.सी., सी.एच.सी. तथा जिला चिकित्सालयों में पीड्रियाट्रिशियन, नर्सेज तथा पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

स्वयं तैयारियों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री

इन रोगों के नियंत्रण में शिथिलता व लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिगणों व अधिकारियों को रोग प्रभावित जनपदों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी जुलाई माह में निरीक्षण करेंगे।

साफ–सफाई पर विशेष ध्यान

इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जनपदों में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। समस्त उपचार केन्द्रों पर औषधियों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था होगी। दवाओं और बेड की व्यवस्था में कमी नहीं होगी

तुरन्त काम करेगी रैपिड रेस्पॉन्स टीम

रैपिड रेस्पॉन्स टीम रोग की जानकारी मिलते ही तुरन्त कार्यवाही करेगी। त्वरित व प्रभावी उपचार के लिए दक्ष कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एम्बुलेन्सेज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इनके माध्यम से रोगियों को तुरन्त अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा।

ए.ई.एस., जे.ई. का केन्द्र मात्र गोरखपुर का बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज ही नहीं होगा, बल्कि इनके उपचार की व्यवस्था सी.एच.सी., पी.एच.सी. और जिला चिकित्सालयों पर भी सुनिश्चित होगी। मातृ एवं नवजात शिशु की देखभाल और पोषण के साथ–साथ टीकाकरण की भी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

जागरूकता के लिए चलेगा विशेष अभियान

वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावित जनपदों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मास एवं प्रिण्ट मीडिया, मोबाइल वैन्स के माध्यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वीडियो और डॉक्यूमेण्ट्री फिल्मों के माध्यम से इन रोगों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ■

प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में इन रोगों के नियंत्रण, उपचार की पूरी तैयारी रहेगी, जिससे जे.ई. एवं ए.ई.एस. से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दी जा सके।

– योगी आदित्यनाथ

जनता की सुविधा और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नगरीय बसों का होगा संचालन

आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी

लखनऊ की जनसंख्या एवं लोगों के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत नगरीय परिवहन प्रणाली का विकास

इलाहाबाद की आवश्यकता विशेषकर कुम्भ-2019 के दृष्टिगत होगा नगरीय बसों का संचालन

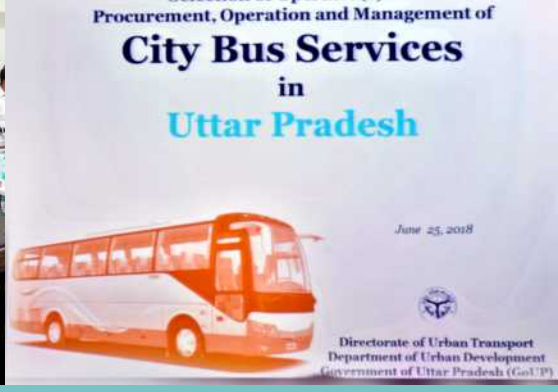

लखनऊ तथा इलाहाबाद में चलेगी पर्यावरण अनुकूल नगरीय बसें

जनता की सुविधा और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नगरीय बसों का संचालन किए जायेगा। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे कम लागत में बसों का संचालन हो सकेगा और यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होगा। साथ ही, इससे प्रदूषण को भी रोका जा सकेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगरीय परिवहन प्रणाली के अन्तर्गत लखनऊ तथा इलाहाबाद में नगरीय बसों के संचालन के सम्बन्ध में किए गए प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगरीय बसों के संचालन को योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाए डीजल व पेट्रोल पर आधारित परिवहन के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्यवाही की जाए।

लखनऊ की जनसंख्या एवं लोगों के आवागमन की सुविधा के मद्देनजर नगरीय परिवहन प्रणाली विकसित की जायेगी। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में भी वहां की आवश्यकता विशेषकर कुम्भ–2019 के दृष्टिगत नगरीय बसों के संचालन किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। वाराणसी में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

मानवीय सृष्टि का आधार नदी संस्कृति है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, वे सभी किसी न किसी नदी के तट पर पनपी हैं। स्वच्छता जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसलिए नदियों को सभी प्रकार की गन्दगी से बचाना होगा। इनकी अविरलता और निर्मलता बनाये रखना, भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करना यह मानवीय सृष्टि और जीव सृष्टि के हित में आवश्यक है।

मुख्यमंत्री जी का संकल्प
निर्मल होगी गोमती

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में गोमती तट पर स्थित झूलेलाल वाटिका पर 'गोमती नदी सफाई महा अभियान' के शुभारम्भ अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को सफाई की शपथ भी दिलायी।

मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के उपरान्त गोमती तट पर पहुंचकर स्वयं सफाई अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित वृक्ष भण्डारे के तहत उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास, पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी सहित कई गणमान्य नागरिकों को पौधे वितरित किए।

गोमती नदी की सफाई के इस महा अभियान से लोगों एवं संस्थाओं को जोड़ा गया है, ताकि इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से किया जा सके और इस कार्य में लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा सके। इस महाअभियान के माध्यम से समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ लोगों को नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ■

बेटियों से न करें भेदभाव : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जी ने स्व. राम प्रकाश त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने खनन, मद्यनिषेध एवं आबकारी राज्यमंत्री श्रीमती अर्चना पाण्डेय के संदर्भ में कहा कि एक पुत्री ने जिस कर्मठता और मजबूती के साथ अपने पिता स्व. राम प्रकाश त्रिपाठी की विरासत को नई उँचाइयों की ओर पहुंचाया है, उससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। बेटा हो या बेटी अगर कोई भेदभाव न हो तो बेटी भी भरपूर सम्भावनाओं को जन्म दे सकती है। समाज में उन लोगों के लिये इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा दी जा रही है कि यदि पुत्रियों को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल रहा है गरीब जनता को

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ गरीब जनता तक पहुंच रहा है। वर्तमान सरकार जाति, वर्ग, मजहब के लिये नहीं बल्कि गरीब जनता के हित के लिये काम कर रही है। पिछले चार वर्षों के दौरान भारत सरकार की लगभग 100 योजनाओं को संचालित कर गरीब जनता को लाभान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार कन्नौज में स्व. राम प्रकाश त्रिपाठी की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये।

गरीब जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है सरकार

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की कई नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले अविश्वास का वातावरण था। भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच चुका था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा समाप्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार किसी विशेष जाति, वर्ग, मजहब के लिये नहीं बल्कि गरीब जनता के हितों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर उन्हें लाभान्वित कर रही है।

चौपाल लगाकर गांव-गांव में पहुंचाई जा रही योजनायें

गांव-गांव चौपाल लगाकर उज्ज्वला, आयुष्मान, जनधन, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में जनता को जागरूक कर लाभान्वित किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में इलाज के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी, जिससे गरीब जनता अच्छे अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का उपचार करा सके। गरीब पात्र व्यक्तियों को आवास, रोजगार, सुरक्षा, शौचालय, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन आदि से आच्छादित किया जा रहा है।

विगत एक वर्ष में 3500 करोड़ आय हुई खनन से

पूर्व में 1400 करोड़ रुपये की धनराशि खनन से प्राप्त होती थी, जबकि विगत एक वर्ष में 3500 करोड़ रुपये की आय हुई है। ■

27 जून 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मगहर में स्थापित होगी संत कबीर अकादमी

जनपद संत कबीर नगर में संत कबीर जी की समाधि स्थल मगहर में संत कबीर अकादमी की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। अकादमी के निर्माण हेतु रूपये 250 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

संत कबीर के जीवन और दर्शन पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध, सर्वेक्षण, प्रकाशन और प्रदेर्शन हेतु संत कबीर अकादमी का गठन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत एक संत कबीर पुस्तकालय की स्थापना भी की जायेगी, जिसमें संत कबीर द्वारा सचित समस्त कृतियों, शोध संदर्भो, प्रकाशनों तथा पाण्डुलिपियों का संगंह किया जायेगा।

- लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि में पांच हजार की बढ़ोत्तरी, मिलेंगी नि:शुल्क परिवहन एवं स्वास्थ्य सुविधायें
- 'पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे' के टेण्डर मसौदे को स्वीकृति, निर्धारित समय से पहले पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि
- औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरण विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे ग्राम सभा की भूमि का अधिग्रहण
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के घरेलू भत्ते में बढ़ोत्तरी
- बन्द होगी यू.पी. पावर कारपेरेशन की शेल कम्पनी

28 हजार सरकारी विद्यालयों में लगेगें आरओ प्लांट, बच्चे पीएंगे साफ पानी

वाटर ए.टी.एम. योजनान्तर्गत बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल के सात ए.ई.एस. तथा जे.ई. प्रभावित जनपदों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों अर्थात् कुल 14 जनपदों के 28041 सरकारी एवं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 लीटर भण्डारण क्षमता के एक–एक 'अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र' की स्थापना से शुद्ध प्रेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस पर लगभग 71 करोड़ 50 लाख 46 हजार रूपये की लागत आएगी। प्लांट लगाने के उपरान्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को हस्तांतरित किये जायेंगे। आपूर्तिकर्ता फर्म 5 वर्ष तक प्लांट का रखरखाव करेगी।

सरकार के इस निर्णय से छात्र–छात्राओं को विद्यालय में ही शुद्ध पेयजल मिल सकेगा और ए.ई.एस./जे.ई. जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

पिछड़े वर्ग को विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से मिलेगा स्वरोजगार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाने में सहायता करेगा।

योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को बढ़ईगिरी, प्लम्बरिंग, सुरक्षा गार्ड, मेडिकल नर्सिंग, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, बिजली मोटर रिपेयरिंग, राज मिस्त्री, बिजली के छोटे–छोटे सामान बनाने एवं रिपेयरिंग का कार्य, बांस–बेंत, कालीन एवं दरी बुनाई, बोरिंग मिस्त्री, लेथ मशीन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, साड़ियों की छपाई–कढ़ाई, टेलरिंग, तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य ट्रेडों का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी नया उद्यम स्थापित एवं पूर्व संचालित उद्यम का विकास कर सकेंगे। उन्हें नवीन उद्यम स्थापाना हेतु बैंकों से सरलता से लोन मिल सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछड़े वर्ग के लगभग 1050व्यक्तियों को लाभाान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों का होगा सर्वेक्षण, मिलेगा योजनाओं का लाभ

सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना–2011 की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रहे निर्धन, असहाय, दलित, दिव्यांग, तथा पिछड़े वर्ग के पात्र व्यक्तियों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सर्वे कराया जायेगा। यह सर्वे कार्य लगभग तीन माह तक चलेगा और इसके अन्तर्गत पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, अन्त्योदय राशन कार्ड, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री आवास सोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का सर्वेक्षण कराया जायेगा। ग्राम स्वराज अभियान की चौपालों से मिले फीडबैक के उपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी